शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

माह नवंबर, 2024 हेतु मंत्रिमंडल का मासिक सारांश :
नवंबर, 2024 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(i) क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: एशिया 2025 जिसमें दो संस्थान - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटीडी) 44वें और आईआईटी बॉम्बे 48वें स्थान पर - शीर्ष 50 में शामिल हैं, से पता चलता है कि भारत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके अतिरिक्त, पांच और संस्थान जैसे आईआईटी मद्रास (56), आईआईटी खड़गपुर (60), भारतीय विज्ञान संस्थान (62), आईआईटी कानपुर (67), और दिल्ली विश्वविद्यालय (81) को शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है, जो देश की शैक्षणिक क्षमता दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय (120), यूपीईएस (148), और वीआईटी (150) जैसे संस्थान भारत की उच्च शिक्षा की गहराई और गुणवत्ता को दर्शाते हैं।

(i i) आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, तथा शिक्षा मंत्रालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत आयुर्विज्ञान संस्थान (आईएमएस), बीएचयू को संवर्धित वित्तपोषण और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहयोग हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अनुसंधान के भविष्य को पुनर्परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

(iii) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 06.11.2024 को केंद्रीय क्षेत्र के तहत एक नई पहल पीएम-विद्यालक्ष्मी को मंजूरी प्रदान की है, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वित्तीय बाधाएं उच्च शिक्षा तक पहुंच में बाधा न बनें। 3,600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, यह योजना बिना किसी जमानत के शिक्षा ऋण प्रदान करती है तथा 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलती है। इस योजना से प्रतिवर्ष 22 लाख से अधिक छात्रों के लाभान्वित होने की उम्मीद है, जिससे उन्हें देश भर के शीर्ष 860 उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में प्रवेश मिल सकेगा।

(iv) दिनांक 12 नवंबर 2024 को, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने एनईपी 2020

को लागू करने के लिए विभिन्न संकल्पनाओं और कार्य-प्रणालियों का प्रसार करने हेतु नई दिल्ली में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों के साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा संबंधी दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

(v) केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 25.11.2024 को 'एक राष्ट्र एक सदस्यता (ओएनओएस)' नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी गई, जो सरकार द्वारा प्रबंधित उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) संस्थानों के छात्रों, संकायों और शोधकर्ताओं को उच्च प्रभाव वाले शैक्षिक अनुसंधान लेखों और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करेगी। अगले तीन वर्षों के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

(vi) भारत सरकार ने बजट वर्ष 2022-23 में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य देशभर के छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान करना है, साथ ही व्यक्तिगत अधिगम अनुभव के साथ उन्हें उनके घर पर शिक्षा सुलभ कराना है। ई-विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु पीआईबी/सीईई नोट को कुल 537.80 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ पर वित्त सचिव और सचिव (व्यय), व्यय कार्यालय, वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 24.04.2023 को स्थापना व्यय (सीईई) - सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) संबंधी संयुक्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। डिजिटल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 नामक एक विधेयक विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के परामर्श से तैयार किया गया है। संसद में डिजिटल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 पेश करने और विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी मानदंडों के अनुसार स्तर 14 और उससे ऊपर के ग्यारह पदों के सृजन हेतु मंत्रिमंडल के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

(vii) शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से दिनांक 9 और 10 नवंबर को आईआईटी हैदराबाद में राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। इस सम्मेलन में देश भर के केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों (सीएफआई) के लगभग 350 हितधारक एकत्रित हुए। इनमें छात्र, संकाय, सरकारी अधिकारी और नीति निर्माता शामिल थे। यह आयोजन शैक्षिक परिवेश में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, दृढ़ता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित था, जिसमें विशेष रूप से परिसर में छात्रों के कल्याण हेतु एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह एक महत्वपूर्ण पहल थी क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण परिदृश्य के मुद्दे ने सार्वजनिक चर्चा में इतना अधिक ध्यान आकर्षित किया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 "माइंडिंग द माइंड: टेकिंग स्टॉक ऑफ द मेंटल हेल्थ सिनेरियो" में इस पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है, जिसमें सिफारिश की गई है कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान देना स्वास्थ्य

और आर्थिक दोनों रूप से अनिवार्य है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया।

***